Pariksha Saathi — दैनिक करंट अफेयर्स

28 अक्टूबर 2026 • हिंदी

SSC CGL • CHSL • MTS • IBPS PO/Clerk • SBI PO/Clerk • RRB — 19 खबरें + 5 प्रश्न • स्रोत: PIB (सभी खबरें आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों से)

1 भारत और मैक्सिको ने संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर कर तरजीही व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से वार्ता शुरू की

India and Mexico sign the Terms of Reference, formally launching negotiations for a Preferential Trade Agreement

SSC • Banking • General

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2026 को बताया कि भारत और मैक्सिको ने तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) पर वार्ता के लिए संदर्भ की शर्तों (टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर सृजित करने के उद्देश्य से होने वाली वार्ताओं का ढांचा, दायरा, तौर-तरीके और रोडमैप तय करती हैं। इन पर हस्ताक्षर के साथ एक पारस्परिक रूप से लाभकारी और संतुलित पीटीए के लिए औपचारिक रूप से वार्ता शुरू हो गई है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने, व्यावसायिक अवसर सृजित करने, निवेश प्रवाह बढ़ाने और सुदृढ़ एवं विविधीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं में योगदान देने की क्षमता है। यह पहल जून 2025 में कनाडा में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति डॉ. क्लाउडिया शीनबाम की मुलाकात में बनी सहमति के बाद की गई है, जब दोनों नेताओं ने भारत-मैक्सिको साझेदारी को और मज़बूत तथा गहरा करने पर सहमति व्यक्त की थी। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल की यात्रा के दौरान दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार एवं निवेश प्रवाह के विस्तार के अवसरों पर चर्चा की; यह चर्चा मैक्सिको के विदेश व्यापार उप-मंत्री (अंडरसेक्रेटरी ऑफ़ फ़ॉरेन ट्रेड) लुइस रोसेन्डो गुतिएरेज़ रोमानो के साथ हुई, जिन्होंने अर्थव्यवस्था मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ़ इकोनॉमी) मार्सेलो एब्रार्ड कासाउबोन की ओर से भाग लिया। संदर्भ की शर्तों में प्रमुख वार्ता क्षेत्र शामिल हैं, जैसे वस्तुओं के लिए बाज़ार पहुंच, उत्पत्ति के नियम, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और व्यापार सुविधा, विवाद निपटान, स्वच्छता एवं पादप-स्वच्छता उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं और व्यापार उपचार। प्रस्तावित समझौते का उद्देश्य दोनों अर्थव्यवस्थाओं की पूरकताओं का लाभ उठाना है; रिलीज़ के अनुसार वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से मज़बूत जुड़ाव वाला मैक्सिको भारतीय निर्यातकों और निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाज़ार है, और सहयोग की महत्वपूर्ण संभावना वाले क्षेत्रों में ऑटोमोटिव, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि-खाद्य, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, चिकित्सा उपकरण और उन्नत विनिर्माण शामिल हैं। दोनों पक्षों ने 2027 की पहली तिमाही के दौरान भारत में एक मैक्सिकन व्यावसायिक मिशन आयोजित करने की संभावना पर भी चर्चा की।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329303

2 कूनो राष्ट्रीय उद्यान के चीते KNG22 की आग्नेयास्त्र के छर्रों से लगी चोटों के कारण मृत्यु की जांच के लिए केंद्र ने उच्च-स्तरीय दल भेजा

Centre deputes a high-level team to investigate the death of cheetah KNG22 of Kuno National Park from firearm pellet injuries

SSC • Railway • Environment • General

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2026 को बताया कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के 19 महीने के नर चीते (KNG22) की आग्नेयास्त्र (फायरआर्म) के छर्रों से लगी चोटों के कारण हुई मृत्यु को गंभीरता से लिया है, और प्रोजेक्ट चीता के अत्यंत महत्व तथा पुनर्स्थापित चीतों की आबादी की सुरक्षा के उच्चतम मानक सुनिश्चित करने की आवश्यकता को देखते हुए घटना की ज़मीनी जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय दल भेजा है। केंद्रीय दल में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के वन महानिरीक्षक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) के अपर निदेशक और डब्ल्यूसीसीबी के क्षेत्रीय उप निदेशक शामिल हैं; इसे चीते की मृत्यु की परिस्थितियों की गहन जांच करने, सभी उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल करने और कड़ी व त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश वन विभाग के साथ निकट समन्वय करने का दायित्व सौंपा गया है। चीता निरवा की संतान यह चीता 25 अक्टूबर 2026 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र के बाहर मुरैना के क्षेत्रीय (टेरिटोरियल) वनों में घायल अवस्था में मिला था; मध्य प्रदेश वन विभाग के अनुसार उसी दिन उसे श्योपुर क्षेत्रीय वन मंडल से रेस्क्यू कर जबलपुर स्थित पशु चिकित्सा सुविधा में गहन पशु चिकित्सा देखभाल और आपातकालीन सर्जरी दी गई, और सर्जरी के दौरान उसके शरीर से आग्नेयास्त्र के पांच छर्रे निकाले गए। चिकित्सा प्रयासों के बावजूद 27 अक्टूबर 2026 को चीते की मृत्यु हो गई, और चिकित्सा जांचों में निकाले गए छर्रों से जुड़ी कई आंतरिक चोटों की पुष्टि हुई। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए वन और पुलिस अधिकारियों वाला एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) पहले ही गठित कर दिया है। केंद्रीय दल राज्य तंत्र के साथ समन्वय में काम करेगा, सुरक्षा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन तथा भविष्य में ऐसी किसी घटना से बचने के लिए किए जा रहे निगरानी और संरक्षण उपायों की भी पड़ताल करेगा, और राज्य सरकार तथा क्षेत्रीय प्राधिकारियों को आगे के निर्देश देने के लिए अपने निष्कर्ष और सिफारिशें मंत्रालय को सौंपेगा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329277

3 हरित हाइड्रोजन पर PIB पृष्ठभूमि टिप्पणी: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक कम से कम 5 एमएमटी वार्षिक उत्पादन क्षमता

PIB backgrounder on green hydrogen: the National Green Hydrogen Mission targets at least 5 MMT of annual production capacity by 2030

SSC • Railway • Environment • General

PIB की 28 अक्टूबर 2026 की पृष्ठभूमि टिप्पणी 'हरित हाइड्रोजन: भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े परिवर्तन का उभरता हुआ स्तंभ' में हरित हाइड्रोजन को नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके जल के विखंडन से, मुख्य रूप से इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए, बनाया जाने वाला हाइड्रोजन बताया गया है, और कहा गया है कि यह उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम शोधन, लोहा एवं इस्पात, भारी (हेवी-ड्यूटी) सड़क परिवहन और शिपिंग जैसे उत्सर्जन कम करने में कठिन (हार्ड-टू-एबेट) क्षेत्रों में उत्सर्जन घटाने में मदद कर सकता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा अगस्त 2023 में अधिसूचित भारत के हरित हाइड्रोजन मानक के अनुसार हाइड्रोजन तभी हरित माना जाता है जब 12 महीने के औसत के आधार पर, वेल-टू-गेट (उत्पादन स्रोत से संयंत्र के गेट तक) स्तर पर, उसका उत्सर्जन प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन 2 किलोग्राम CO2 समतुल्य से अधिक न हो; पृष्ठभूमि टिप्पणी के अनुसार इसके साथ भारत हरित हाइड्रोजन को औपचारिक रूप से परिभाषित करने वाले शुरुआती कुछ देशों में शामिल हो गया। एमएनआरई भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स (उत्पादों) का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) लागू कर रहा है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी थी; इसका लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) उत्पादन क्षमता है, जो निर्यात मांग के साथ प्रति वर्ष 10 एमएमटी तक पहुँच सकती है। इसका 'स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांज़िशन' (एसआईजीएचटी) कार्यक्रम, जिसका 2029-30 तक का परिव्यय 17,490 करोड़ रुपये है, घरेलू इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देता है। 15 कंपनियों को प्रति वर्ष 3,000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण क्षमता के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं, प्रति वर्ष 8,62,000 टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता के लिए भी प्रोत्साहन दिए गए हैं, तथा फ़रवरी 2026 तक प्रति वर्ष लगभग 8,000 टन हरित हाइड्रोजन क्षमता शुरू (कमीशन) हो चुकी थी। एमएनआरई ने दीनदयाल पोर्ट (कांडला, गुजरात), वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट (तूतीकोरिन, तमिलनाडु) और पारादीप पोर्ट (ओडिशा) को हब के रूप में मान्यता दी है, और चार हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर (एचवीआईसी) प्रदान किए गए हैं: जोधपुर, ओडिशा, पुणे और केरल। 31 दिसंबर 2030 तक शुरू होने वाले हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया संयंत्रों को 25 वर्षों के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) शुल्क से छूट दी गई है, और एमएनआरई ने अप्रैल 2025 में 'ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया' शुरू की, जिसके तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) निगरानी, सत्यापन और प्रमाणन के लिए एजेंसियों को मान्यता देता है। पृष्ठभूमि टिप्पणी में यह भी बताया गया है कि भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन-चालित ट्रेन का उद्घाटन 17 जुलाई 2026 को जींद-सोनीपत खंड पर किया गया, और छह राज्यों (गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल) ने हरित हाइड्रोजन के लिए अपनी विशेष नीतियाँ अधिसूचित की हैं। इस मिशन से जीवाश्म ईंधन के संचयी आयात में 2030 तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की कमी आने, 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जुटने और 6 लाख से अधिक रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है, और लक्षित मात्रा में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग से सालाना लगभग 50 एमएमटी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन टल सकता है; यह 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329321

4 भारत की नए युग की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों पर PIB पृष्ठभूमि टिप्पणी: स्पेसडेक्स से भारत अंतरिक्ष डॉकिंग का प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बना; एनजीएलवी निम्न पृथ्वी कक्षा में 30 टन तक के लिए डिज़ाइन

PIB backgrounder on India's new-age space technologies: SpaDeX made India the fourth country to demonstrate space docking; NGLV designed for up to 30 tonnes to Low Earth Orbit

SSC • Railway • Science • General

PIB की 28 अक्टूबर 2026 की पृष्ठभूमि टिप्पणी 'भारत के नए युग की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां: आत्मनिर्भरता की राह' में 21 नवंबर 1963 को केरल के थुम्बा से प्रक्षेपित पहले साउंडिंग रॉकेट से लेकर प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा का विवरण दिया गया है। भारत की संगठित अंतरिक्ष गतिविधियाँ 1962 में डॉ. विक्रम ए. साराभाई के दृष्टिकोण के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (इनकोस्पार) की स्थापना के साथ शुरू हुईं; इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ, जिसने इनकोस्पार का स्थान लिया, और 1972 में इसे अंतरिक्ष विभाग के अधीन लाया गया। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8,240 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वीकृत अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी) - जिस परिव्यय में विकास लागत, तीन विकासात्मक उड़ानें, आवश्यक सुविधाएँ, कार्यक्रम प्रबंधन और प्रक्षेपण अभियान शामिल हैं - निम्न पृथ्वी कक्षा (एलईओ) में अधिकतम 30 टन की क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एलवीएम3 की 10 टन की एलईओ सीमा का तिगुना है; 14 टन एलईओ पेलोड क्षमता वाला एनजीएलवी का आंशिक रूप से पुन: प्रयोज्य संस्करण भी विकसित किया जा रहा है। इसरो ने अपने पंखों वाले पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (आरएलवी) प्रौद्योगिकी प्रदर्शक 'पुष्पक' के तीन लैंडिंग प्रयोग 2 अप्रैल 2023, 22 मार्च 2024 और 23 जून 2024 को पूरे किए, और भारत ने 28 अगस्त 2016 को अपने स्क्रैमजेट का उड़ान परीक्षण किया, जिसमें मैक 6 की गति हासिल हुई। 27 मार्च 2025 को इसरो ने अपने स्वदेशी 300 mN स्टेशनरी प्लाज़्मा थ्रस्टर का 1,000 घंटे का जीवन परीक्षण पूरा किया, जिसे वह अपने प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह (TDS-01) पर परखने की योजना बना रहा है। इसरो के स्पेसडेक्स (SpaDeX) मिशन ने 16 जनवरी 2025 को पहली बार अपने दो उपग्रहों को डॉक किया, 20 अप्रैल 2025 को 15 मीटर की अंतर-उपग्रह दूरी से पूर्ण स्वायत्तता के साथ दूसरी डॉकिंग पूरी की और 21 अप्रैल 2025 को डॉक किए गए उपग्रहों के बीच द्विदिशीय बिजली हस्तांतरण का प्रदर्शन किया; पृष्ठभूमि टिप्पणी के अनुसार इसके साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष डॉकिंग का प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बन गया। पृष्ठभूमि टिप्पणी में भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली नाविक (NavIC) का भी उल्लेख है, जो पूरे भारत में और भारतीय मुख्य भूमि से 1,500 किलोमीटर आगे तक स्थिति, नेविगेशन और समय सेवाएँ देती है; साथ ही 2 नवंबर 2025 को प्रक्षेपित भारतीय नौसेना के समर्पित संचार उपग्रह सीएमएस-03 (जीसैट-7आर) का, और नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (निसार) मिशन का, जिसे 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी-एफ16 द्वारा प्रक्षेपित किया गया और जो दो रडार आवृत्तियों - नासा के एल-बैंड और इसरो के एस-बैंड - का एक साथ उपयोग करने वाला पहला उपग्रह मिशन है। अंतरिक्ष विभाग के अनुसार भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 2033 तक 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य है; न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) ने इसरो द्वारा विकसित 83 प्रौद्योगिकियों को भारतीय उद्योग को हस्तांतरित करने के लिए 118 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, और 31 मार्च 2026 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्ट-अप में संचयी निवेश लगभग 618.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329355

5 केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने वैज्ञानिक भूजल पुनर्भरण नियोजन के लिए राष्ट्रीय जल मिशन के सहयोग से बीआईएसएजी-एन द्वारा विकसित 'पुनःभरण' मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया

Union Jal Shakti Minister launches the Punah Bharan mobile application, developed by BISAG-N with the National Water Mission, for scientific groundwater recharge planning

SSC • Railway • Environment • General

जल शक्ति मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2026 को बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने वैज्ञानिक भूजल पुनर्भरण नियोजन में सहायता के लिए 'पुनःभरण' मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है, जिसे बीआईएसएजी-एन ने जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग के राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) के सहयोग से विकसित किया है। यह मोबाइल एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं को 3 किलोमीटर तक की त्रिज्या (रेडियल दूरी) के भीतर संभावित कृत्रिम पुनर्भरण क्षेत्रों की पहचान करने और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर उपयुक्त पुनर्भरण संरचनाओं का पता लगाने में सक्षम बनाता है। रिलीज़ के अनुसार वेब पोर्टल ग्राम-स्तरीय कृत्रिम पुनर्भरण संरचना (एआरएस) ज़ोनिंग मानचित्रों, जीआईएस उपकरणों और विषयगत परतों (थीमैटिक लेयर्स) तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे सतत भूजल प्रबंधन के लिए सोच-समझकर योजना बनाने में सहायता मिलती है। यह प्लेटफ़ॉर्म वर्षा, भूजल स्तर, भूजल उत्पादन (यील्ड), ढलान और जल निकासी सहित भू-स्थानिक डेटासेट का उपयोग करता है, ताकि संभावित पुनर्भरण क्षेत्रों की पहचान करने और उपयुक्त हस्तक्षेपों की योजना बनाने में मदद मिल सके। मंत्रालय ने 'पुनःभरण' को भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैज्ञानिक भूजल पुनर्भरण नियोजन को आगे बढ़ाने वाला बताया।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329354

6 एनएचआरसी ने 'महिला कैदियों और उनके बच्चों के मानवाधिकारों के संरक्षण' पर एडवाइजरी जारी की, दो महीने के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी

NHRC issues an Advisory on the 'Protection of Human Rights of Female Inmates and their Children', seeks Action Taken Reports within two months

SSC • Police • General

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 28 अक्टूबर 2026 को बताया कि उसने 'महिला कैदियों और उनके बच्चों के मानवाधिकारों के संरक्षण' पर एक एडवाइजरी नौ केंद्रीय मंत्रालयों तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को जारी की है। आयोग ने ज़ोर दिया कि कैदियों के अधिकारों और ज़रूरतों पर - जिनमें महिला कैदी और उनके बच्चे शामिल हैं, जो कैदियों के बीच एक अधिक असुरक्षित (वल्नरेबल) समूह हैं - केंद्रित ध्यान और संवेदनशील, जेंडर-अनुकूल (जेंडर-रिस्पॉन्सिव) दृष्टिकोण की आवश्यकता है; हिरासत संबंधी सुरक्षा उपायों से आगे, उसने मानवीय जेल परिस्थितियों, पर्याप्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, न्याय तक पहुँच, पारिवारिक संबंधों के संरक्षण, बच्चों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा, तथा पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण के सार्थक अवसरों का आह्वान किया। एडवाइजरी कार्रवाई के दस व्यापक क्षेत्रों पर केंद्रित है: जेल प्रणाली में प्रवेश-पूर्व स्थिति, गिरफ़्तारी और प्रवेश; प्रवेश रिकॉर्ड, बाल डेटाबेस और दस्तावेज़ीकरण; स्वास्थ्य, चिकित्सा देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ; महिला कैदी: रहन-सहन की परिस्थितियाँ, स्वच्छता, कल्याण और संवेदीकरण; कैदियों के साथ रह रहे या उनसे अलग हुए बच्चे; संवाद, मुलाकात और पारिवारिक संपर्क; जेल प्रशासन, विधिक सहायता और न्याय तक पहुँच; महिला कैदियों की अदालत में पेशी के दौरान जेंडर-अनुकूल सुविधाएँ और कल्याणकारी उपाय; पुनर्वास, रिहाई के बाद की स्थिति और सामाजिक पुनः एकीकरण; तथा विदेशी नागरिक कैदी। एनएचआरसी ने सभी संबंधित प्राधिकारियों से एडवाइजरी की सिफ़ारिशों को लागू करने और हुई प्रगति से उसे अवगत कराने के लिए दो महीने के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने का आग्रह किया है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329351

7 पीयूष गोयल ने भारत की राजकीय यात्रा पर आए लिकटेंस्टीन के हेरेडिटरी प्रिंस एलॉइस से मुलाकात की; बातचीत भारत-ईएफटीए टीईपीए के तहत निवेश पर केंद्रित

Piyush Goyal meets Hereditary Prince Alois of Liechtenstein during the Prince's State Visit to India; talks focus on investment under the India-EFTA TEPA

SSC • Banking • General

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 28 अक्टूबर 2026 को भारत की राजकीय यात्रा पर आए लिकटेंस्टीन के हेरेडिटरी प्रिंस महामहिम (H.S.H.) एलॉइस से शिष्टाचार भेंट की; बैठक का केंद्र भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के तहत आर्थिक जुड़ाव को मज़बूत करना और निवेश के अवसरों को आगे बढ़ाना था। गोयल ने भारत की मज़बूत आर्थिक बुनियाद, निरंतर सुधार एजेंडा और बढ़ती विनिर्माण क्षमताओं तथा कारोबारी सुगमता बढ़ाने के सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। रिलीज़ के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह 843 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, और वित्त वर्ष 2025-26 में यह प्रवाह रिकॉर्ड 94.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा, तथा भारत में 2.50 लाख स्टार्टअप 770 से अधिक ज़िलों और 56 उद्योगों में 25.42 लाख से अधिक रोज़गार दे रहे हैं, जिनमें से 52% स्टार्टअप गैर-महानगरीय शहरों में हैं। गोयल ने 1 अक्टूबर 2025 को लागू हुए भारत-ईएफटीए टीईपीए से मिलने वाले अवसरों पर प्रकाश डाला; इस समझौते में प्रावधान है कि ईएफटीए देश 15 वर्षों में भारत में एफडीआई में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि करने और दस लाख प्रत्यक्ष रोज़गार के सृजन में सहायता करने का लक्ष्य रखेंगे। उन्होंने लिकटेंस्टीन की कंपनियों को विनिर्माण साझेदारी, प्रौद्योगिकी सहयोग, अनुसंधान एवं विकास, तथा भारतीय आपूर्तिकर्ताओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के साथ गहरे एकीकरण सहित भारत में अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया, और चर्चा में प्रिसिजन इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण, औद्योगिक प्रौद्योगिकियों और नवाचार जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार हुआ। रिलीज़ में याद दिलाया गया कि 7 अक्टूबर 2026 को भारत-ईएफटीए टीईपीए की पहली वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में भारत-ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन (India-EFTA Prosperity Summit) आयोजित हुआ था, जिसमें लिकटेंस्टीन के गृह, अर्थव्यवस्था और खेल मंत्री ह्यूबर्ट ब्यूशेल (Hubert Büchel) ने लिकटेंस्टीन के व्यवसायों के प्रतिनिधियों के साथ भाग लिया था।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329411

8 मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2039-40 तक 10,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय वाली कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना को मंज़ूरी दी

Cabinet approves the Container Manufacturing Promotion Scheme with a budgetary outlay of Rs 10,000 crore up to FY 2039-40

SSC • Banking • Railway • General

PIB की 28 अक्टूबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2039-40 तक 10,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना (सीएमपीएस) को मंज़ूरी दी है। इस योजना में भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने, आयात पर निर्भरता घटाने और आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता (रेज़िलिएंस) बढ़ाने की परिकल्पना है, और इसका उद्देश्य नई विनिर्माण इकाइयों के साथ-साथ मौजूदा कंटेनर विनिर्माण इकाइयों के विस्तार को भी सहायता देना है। रिलीज़ के अनुसार कंटेनर विनिर्माण योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। रिलीज़ में योजना के तीन प्रमुख घटक बताए गए हैं: 859 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली ब्याज सबवेंशन सहायता (इंटरेस्ट सबवेंशन असिस्टेंस - आईएसए), जिसके तहत कंटेनर निर्माताओं द्वारा ग्रीनफ़ील्ड कंटेनर विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने और मौजूदा क्षमताओं के ब्राउनफ़ील्ड विस्तार के लिए लिए गए पात्र टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज सबवेंशन दी जाएगी; 8,891 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली परिचालन व्यय सहायता (ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर असिस्टेंस - ओईए), जिसके तहत वैश्विक शिपिंग मानकों के अनुसार निर्मित और पात्र कंटेनर निर्माताओं द्वारा बेचे गए सभी कंटेनरों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि लागत का अंतर पाटा जा सके और घरेलू स्तर पर निर्मित कंटेनरों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े; और 150 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली परीक्षण एवं प्रमाणन सहायता, जो डायनामिक लॉन्गिट्यूडिनल इम्पैक्ट टेस्टिंग जैसी साझा सुविधाओं की स्थापना में मदद करेगी। योजना से वार्षिक घरेलू कंटेनर विनिर्माण क्षमता के लगभग दस गुना बढ़कर 7.5 लाख टीईयू (ट्वेंटी-फ़ुट इक्विवेलेंट यूनिट) तक पहुँचने; अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण आधार बनने, जिससे भारत के गुणवत्तापूर्ण शिपिंग कंटेनरों के वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में उभरने की संभावना बने; भारत की समुद्री और लॉजिस्टिक्स आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुदृढ़ता बढ़ने; और अनुमानित 3,000 प्रत्यक्ष तथा 50,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने की परिकल्पना है; इससे कॉर्नर कास्टिंग, विशेष इस्पात, लकड़ी के फ़्रेम और पेंट जैसे सहायक उद्योगों को भी समर्थन मिलेगा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329476

9 मंत्रिमंडल ने 2026 से 2033-34 की अवधि के लिए 1,856.67 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना को मंज़ूरी दी

Cabinet approves the Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme with an outlay of Rs 1,856.67 crore for 2026 to 2033-34

SSC • Banking • Sports • General

PIB की 28 अक्टूबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026 से 2033-34 की अवधि के लिए 1,856.67 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना को मंज़ूरी दी है। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित इस योजना का उद्देश्य निवेश, विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देना तथा वैश्विक खेल उपकरण क्षेत्र में भारत की स्थिति को मज़बूत करना है, और यह निवेश, प्रौद्योगिकी अंगीकरण, अनुसंधान एवं नवाचार, कौशल विकास, गुणवत्ता प्रमाणन और बाज़ार विकास के लिए लक्षित सहायता के माध्यम से भारत के खेल उपकरण विनिर्माण आधार को मज़बूत करना चाहती है। यह योजना खेलो भारत नीति 2025, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसमें क्लस्टर-आधारित विनिर्माण के लिए समर्पित खेल सामग्री विनिर्माण क्षेत्रों (स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन - एसजीएमज़ेड) के विकास की परिकल्पना है, जहाँ निर्माता, आपूर्तिकर्ता, परीक्षण सुविधाएँ, डिज़ाइन एवं प्रोटोटाइप केंद्र और सहायक उद्यम एक ही स्थान पर होंगे; ये क्षेत्र भव्य (BHAVYA) योजना और एनआईसीडीसी औद्योगिक पार्कों के तहत मौजूदा औद्योगिक बुनियादी ढांचे के साथ अभिसरण के माध्यम से विकसित किए जाएंगे। एंकर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट (मुख्य निवेश सहायता) घटक प्रमुख घरेलू और वैश्विक निर्माताओं, ब्रांडों और खुदरा शृंखलाओं को निर्दिष्ट क्षेत्रों में विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और टर्नओवर लिंक्ड सपोर्ट (टर्नओवर से जुड़ी सहायता) घटक अधिक उत्पादन, क्षमता विस्तार और निरंतर विनिर्माण वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा; इन दोनों के लिए कुल मिलाकर 1,130 करोड़ रुपये का संयुक्त परिव्यय है। योजना एमएसएमई पर ज़ोर देते हुए मौजूदा खेल सामग्री विनिर्माण क्लस्टरों के उन्नयन में, जिसमें साझा सुविधाएँ और साझा बुनियादी ढांचा शामिल हैं, सहायता करेगी; अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों से प्रमाणन प्राप्त करने और उसके नवीनीकरण के लिए निर्माताओं को 105 करोड़ रुपये के परिव्यय से सहायता देगी; खेल उपकरण, सामग्री विज्ञान, सुरक्षात्मक गियर और उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना में सहायता देगी; अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ अभिसरण के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करेगी; स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुरूप स्टार्ट-अप को समर्पित सहायता देगी; कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा उद्योग हितधारकों के सहयोग से कौशल विकास करेगी; और निर्यात संवर्धन मिशन का लाभ उठाते हुए ब्रांडिंग, आउटरीच और बाज़ार विकास के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भारत की उपस्थिति बढ़ाएगी। रिलीज़ के अनुसार योजना के तहत बेहतर नवाचार, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा और विनिर्माण क्षमता खेलो इंडिया और फ़िट इंडिया जैसी पहलों की पूरक होगी, और योजना से भारत के खेल सामग्री के डिज़ाइन, विकास और विनिर्माण के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में स्थापित होने की उम्मीद है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329481

10 मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 7,395.55 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंज़ूरी दी

Cabinet approves the Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana as a Centrally Sponsored Scheme for 2026-27 to 2030-31 with an outlay of Rs 7,395.55 crore

SSC • Railway • General

PIB की 28 अक्टूबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (पीएम वीजीएसवाई) को मंज़ूरी दी है, जिसे विकसित भारत की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप अगली पीढ़ी की शासन परिवर्तन पहल बताया गया है; इसे 2026-27 से 2030-31 तक लागू करने की मंज़ूरी दी गई है, और इसकी अवधि सोलहवें वित्त आयोग की अवधि के साथ समाप्त होगी। योजना का परिव्यय 7,395.55 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 4,869.48 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2,526.07 करोड़ रुपये है। 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ, इसके प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे। योजना ईग्रामस्वराज पोर्टल पर प्रतिवर्ष 2.55 लाख समग्र ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी में सहायता करेगी, जिसके लिए सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों की नियोजन प्रक्रियाओं को एक साझा डिजिटल मंच पर लाया जाएगा; मौजूदा डिजिटल और जनसंपर्क मंचों, ग्राम सभाओं और पंचायतों के अन्य मंचों के ज़रिए प्रत्येक समन्वित जागरूकता अभियान में कम से कम 1 करोड़ नागरिकों तक पहुँचेगी (रिलीज़ के अनुसार सरकारी योजनाओं और राष्ट्रीय पहलों की जानकारी देने के लिए योजना जिन मौजूदा मंचों का उपयोग करेगी, उनमें 17 भारतीय भाषाओं वाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित बहुभाषी, द्विपक्षीय संचार मंच पंचम (PANCHAM) भी शामिल है); क्षमता निर्माण और डिजिटल मार्गदर्शन के माध्यम से प्रतिवर्ष निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों की शासन क्षमताओं को सुदृढ़ करेगी; और बेहतर लेखांकन, सार्वजनिक प्रकटीकरण और स्वयं के स्रोतों से राजस्व (ओएसआर) जुटाने के साथ-साथ ऑडिटऑनलाइन के माध्यम से प्रतिवर्ष कम से कम 2.55 लाख ऑनलाइन ऑडिट योजनाओं की तैयारी और संबंधित ऑडिट को समय पर पूरा करने में सहायता करेगी। योजना के तहत कोई स्थायी पद सृजित नहीं किया जाएगा, हालाँकि राज्य, ज़िला और ब्लॉक स्तर पर आवश्यकता-आधारित संविदात्मक मानव संसाधन लगाए जा सकते हैं। यह योजना सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी, जिनमें भाग IX से बाहर के (नॉन-पार्ट IX) उन क्षेत्रों के ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थान (पारंपरिक स्थानीय निकाय) भी शामिल हैं जहाँ पंचायतें नहीं हैं। रिलीज़ में बताया गया है कि सोलहवें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए लगभग 4.35 लाख करोड़ रुपये के अनुदान की सिफ़ारिश की है। योजना राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम से लागू होगी, जो वार्षिक कार्ययोजनाएँ प्रस्तुत करेंगे; इनका मूल्यांकन और अनुमोदन नामित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति करेगी।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329483

11 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ़िलीपींस के सेबू में 13वें एडीएमएम-प्लस के मौके पर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ वार पीट हेगसेठ से मुलाकात की; दोनों ने 10 वर्षीय भारत-अमेरिका रक्षा रूपरेखा की समीक्षा की

Raksha Mantri Rajnath Singh meets US Secretary of War Pete Hegseth on the sidelines of the 13th ADMM-Plus in Cebu, Philippines; the two review the 10-year India-US Defence Framework

SSC • Railway • Defence • General

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 अक्टूबर 2026 को फ़िलीपींस के सेबू में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) के मौके पर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ वार (युद्ध मंत्री) पीट हेगसेठ के साथ बैठक की, जिसमें भारत-अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी के तहत प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने अपने मूलभूत सुरक्षा समझौतों की मज़बूत प्रगति पर ध्यान दिया और परिचालन तत्परता, प्रौद्योगिकी साझाकरण और रक्षा औद्योगिक एकीकरण में तेज़ी लाने के नए रास्ते तलाशे। क्षेत्रीय सुरक्षा की समीक्षा के दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद को समाप्त करने के अपने संयुक्त संकल्प पर ज़ोर दिया: रक्षा मंत्री ने कहा कि वैश्विक समुदाय को आतंकवादी संगठनों का समर्थन, प्रशिक्षण या वित्त पोषण करने वाले देशों के प्रति समझौताहीन, शून्य-सहिष्णुता (ज़ीरो टॉलरेंस) का दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, और हेगसेठ ने सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई में संयुक्त राज्य अमेरिका की अटूट एकजुटता और पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने 10 वर्षीय भारत-अमेरिका रक्षा रूपरेखा (फ़्रेमवर्क) की प्रगति की समीक्षा की और भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों को रणनीतिक अभिसरण (स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस) के स्तर तक ले जाने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई; चर्चा में सैन्य-से-सैन्य आदान-प्रदान को आगे बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और रक्षा उद्योग सहयोग को गहरा करने के लिए मज़बूत रक्षा आपूर्ति शृंखलाओं को एकीकृत करने के विषय शामिल रहे। एक्स पर एक पोस्ट में राजनाथ सिंह ने 13वें एडीएमएम-प्लस के मौके पर हुई इस बैठक को उत्कृष्ट बताया और भारत-अमेरिका साझेदारी को स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला कहा। एक अलग रिलीज़ में मंत्रालय ने बताया कि राजनाथ सिंह ने उसी दिन सेबू में एडीएमएम-प्लस के मौके पर जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी से भी मुलाकात की, और राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी चर्चा में भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मज़बूत करने के नए रास्ते तलाशे गए।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329441

12 आईएनएस सह्याद्रि भारत-कोरिया गणराज्य नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास के लिए कोरिया गणराज्य के बुसान पहुँचा

INS Sahyadri arrives at Busan, Republic of Korea, for the India-Republic of Korea Navy bilateral exercise

SSC • Railway • Defence • General

रक्षा मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2026 को बताया कि भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्रि भारत-कोरिया गणराज्य नौसेना (आईएन-आरओकेएन) द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेने के लिए 26 अक्टूबर 2026 को कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) के बुसान नौसैनिक बंदरगाह पहुँचा। कोरिया गणराज्य की नौसेना (आरओकेएन) ने जहाज़ का गर्मजोशी से स्वागत किया। बंदरगाह चरण के दौरान दोनों नौसेनाओं के कर्मी पेशेवर संवाद, एक-दूसरे के युद्धपोतों के दौरे (क्रॉस-डेक विज़िट), क्रॉस-ट्रेनिंग गतिविधियों और खेल आयोजनों में भाग लेंगे, और आईएनएस सह्याद्रि के कमांडिंग अधिकारी आरओकेएन के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट करेंगे। बंदरगाह चरण के बाद समुद्र में समन्वित समुद्री गतिविधियाँ होंगी, जिनमें आईएनएस सह्याद्रि और आरओकेएस मुनमु द ग्रेट भाग लेंगे; इनसे परिचालन समन्वय मज़बूत करने, अंतर-संचालन क्षमता (इंटरऑपरेबिलिटी) बढ़ाने और दोनों नौसेनाओं के पेशेवर संबंधों को सुदृढ़ करने के अवसर मिलेंगे। मंत्रालय के अनुसार यह अभ्यास समुद्री सहयोग को मज़बूत करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा में योगदान देने की भारत और कोरिया गणराज्य की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329562

13 खेल और शिक्षा मंत्रालयों ने 'हर कक्षा में खेल मूल्य' टूलकिट के ज़रिए स्वच्छ खेल के मूल्यों को कक्षाओं तक पहुँचाने के लिए यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया

Sports and Education Ministries exchange an MoU with UNESCO to take clean sport values to classrooms through the 'Sports Values in Every Classroom Toolkit'

SSC • Railway • Sports • General

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनेस्को ने बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को 'हर कक्षा में खेल मूल्य' (स्पोर्ट्स वैल्यूज़ इन एवरी क्लासरूम) टूलकिट के ज़रिए देश भर की कक्षाओं तक स्वच्छ खेल के मूल्यों को पहुँचाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान किया; इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने खेल और शिक्षा को जोड़ने की आवश्यकता दोहराई, जिस पर खेलो भारत नीति 2025 में भी ज़ोर दिया गया है। समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) इंडिया के क्लीन स्पोर्ट कॉन्क्लेव में हुआ। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा, खेल और रोज़ाना की कक्षा गतिविधियों के ज़रिए बच्चों में सम्मान, ईमानदारी (इंटेग्रिटी) और निष्पक्षता जैसे मूल्य विकसित करना है, और टूलकिट के वीडियो मॉड्यूल 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएंगे। यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक डॉ. टिम कर्टिस ने इस समझौता ज्ञापन को भारत के साथ यूनेस्को की साझेदारी का नया अध्याय बताया। डॉ. मांडविया ने कहा कि 2025-26 के दौरान नाडा ने 7,000 से अधिक परीक्षण और 350 से अधिक शिक्षा एवं जागरूकता सत्र आयोजित किए, जिनमें 27,000 प्रतिभागी शामिल हुए; राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर और राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान, हैदराबाद में सप्लीमेंट परीक्षण सुविधाएँ अनजाने में होने वाली डोपिंग के मामलों को रोकने में मदद करती हैं; राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम इस वर्ष लागू हुआ; और सरकार डोपिंग से जुड़ी गतिविधियों को अपराध घोषित करने के प्रावधान संसद में लाने की तैयारी कर रही है। प्रल्हाद जोशी ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन शिक्षा और खेल के बीच लंबे समय से चले आ रहे अंतर को दूर करने में मदद करेगा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329464

14 त्वरित अनुमान: सितंबर 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 6.7% की वृद्धि (आधार 2022-23=100); विनिर्माण में 7.6% और बिजली एवं गैस आपूर्ति में 11.2% की वृद्धि

Quick Estimates: India's Index of Industrial Production grows 6.7% in September 2026 (base 2022-23=100), with manufacturing up 7.6% and electricity and gas supply up 11.2%

SSC • Banking • General

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर 2026 को जारी त्वरित अनुमानों (आधार 2022-23=100) के अनुसार सितंबर 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वर्ष-दर-वर्ष 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई; रिलीज़ के अनुसार आईआईपी की संशोधन नीति के तहत बाद में जारी होने वाले आँकड़ों में इन त्वरित अनुमानों में संशोधन होगा। विनिर्माण में 7.6 प्रतिशत और बिजली एवं गैस आपूर्ति में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि रिलीज़ के विवरण I के अनुसार खनन एवं उत्खनन में 6.2 प्रतिशत की गिरावट आई और जल आपूर्ति, सीवरेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आईआईपी का त्वरित अनुमान 124.3 है, जबकि सितंबर 2025 में यह 116.5 था; खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, बिजली एवं गैस आपूर्ति तथा जल आपूर्ति, सीवरेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन के सूचकांक क्रमशः 90.4, 128.0, 128.6 और 146.4 हैं। विनिर्माण क्षेत्र में एनआईसी 2-अंकीय स्तर पर 23 में से 17 उद्योग समूहों ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, और शीर्ष तीन सकारात्मक योगदानकर्ता मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर का विनिर्माण (19.0 प्रतिशत), विद्युत उपकरण का विनिर्माण (33.9 प्रतिशत) तथा रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण (19.9 प्रतिशत) रहे। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार वृद्धि दर प्राथमिक वस्तुओं में 4.0 प्रतिशत, पूंजीगत वस्तुओं में 10.4 प्रतिशत, मध्यवर्ती वस्तुओं में 12.2 प्रतिशत, अवसंरचना/निर्माण वस्तुओं में 7.2 प्रतिशत, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 6.0 प्रतिशत और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में 1.4 प्रतिशत रही; मध्यवर्ती वस्तुएँ, प्राथमिक वस्तुएँ और पूंजीगत वस्तुएँ शीर्ष तीन योगदानकर्ता रहीं। रिलीज़ सितंबर की वृद्धि की तुलना अगस्त 2026 के त्वरित अनुमान की 8.0 प्रतिशत वृद्धि से करती है; अगस्त के सूचकांकों का अब अंतिम संशोधन हो चुका है, और विवरण I में अगस्त 2026 की वृद्धि 7.8 प्रतिशत दर्शाई गई है। विवरण I के अनुसार अप्रैल-सितंबर 2026 में वृद्धि 6.8 प्रतिशत रही। सितंबर के अनुमान 86.5 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर संकलित किए गए हैं, और अक्टूबर 2026 का आईआईपी सोमवार, 30 नवंबर 2026 को जारी होगा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329475

15 एपीडा के सहयोग से जीआई-टैग प्राप्त तंदूर रेडग्राम की पहली निर्यात खेप तेलंगाना से ऑस्ट्रेलिया रवाना

APEDA facilitates the first export shipment of GI-tagged Tandur Redgram from Telangana to Australia

SSC • Banking • General

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने जीआई-टैग प्राप्त तंदूर रेडग्राम की तेलंगाना से ऑस्ट्रेलिया को पहली निर्यात खेप को सुगम बनाया; यह खेप 28 अक्टूबर 2026 को हैदराबाद से हाइब्रिड मोड में रवाना की गई, जिसे तेलंगाना सरकार के कृषि उत्पादन आयुक्त एवं कृषि और सहकारिता विभाग के सचिव सुरेंद्र मोहन तथा एपीडा हैदराबाद के एजीएम आर. पी. नायडू ने वर्चुअल रूप से झंडी दिखाई। 2.5 मीट्रिक टन (एमटी) की यह खेप हैदराबाद की मेसर्स दुर्गा एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स (Durga Exports and Imports) ने 'AMMAAS' ब्रांड नाम से निर्यात की है; इसे समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया की मेसर्स भारतमा पीटीवाई लिमिटेड (Bharathma PTY Ltd) इसका आयात कर रही है। तंदूर रेडग्राम तेलंगाना का पहला कृषि उत्पाद है जिसे भौगोलिक संकेतक (जीआई) पंजीकरण मिला। इसकी खेती मुख्य रूप से तंदूर क्षेत्र के चार मंडलों - तंदूर, बशीराबाद, पेद्देमुल और येलाल - के वर्षा-आधारित इलाकों में होती है, और इसकी विशिष्ट विशेषताएँ क्षेत्र की उपजाऊ गहरी काली मिट्टी, एटापुलगाइट क्ले खनिज भंडारों की उपस्थिति और चूना पत्थर के पर्याप्त भंडारों से जुड़ी हैं। इसमें लगभग 22-24 प्रतिशत प्रोटीन होता है, जो अनाजों की प्रोटीन मात्रा का लगभग तीन गुना है, और यह अपने स्वाद, पकाने की गुणवत्ता और लंबे समय तक सुरक्षित रहने की गुणवत्ता (कीपिंग क्वालिटी) के लिए जाना जाता है। रिलीज़ के अनुसार एपीडा निर्यात संपर्क सुगम बनाकर, व्यापार मेलों में निर्यातकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके और निर्यात अवसरों तथा बाज़ार पहुँच पर मार्गदर्शन देकर अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भारत के जीआई-टैग प्राप्त कृषि उत्पादों के प्रचार में सहयोग करता है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329671

16 प्रधानमंत्री ने प्रगति की 54वीं बैठक की अध्यक्षता की; 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की

PM chairs the 54th PRAGATI meeting; reviews infrastructure projects worth over Rs 16,000 crore across 31 States and UTs

SSC • Railway • General

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 अक्टूबर 2026 को सेवा तीर्थ में प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की 54वीं बैठक की अध्यक्षता की, जो सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन को बढ़ावा देने वाला आईसीटी-आधारित, मल्टी-मॉडल मंच है। यह मंच कार्यान्वयन की अड़चनें दूर करने और परियोजनाओं व कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ लाता है। प्रधानमंत्री ने रेलवे, एकता मॉल और ड्रग पार्क से जुड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की, जो 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में हैं और जिनकी लागत 16,000 करोड़ रुपये से अधिक है; समीक्षा में समय-सीमा, अंतर-एजेंसी समन्वय और मुद्दों के समय पर समाधान पर ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि पीएम एकता मॉल स्थानीय उत्पादों को बाज़ार दें और कारीगरों की आजीविका मज़बूत करें, मॉल को पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों से जोड़ने का आह्वान किया, और मुख्य सचिवों द्वारा इनकी प्रगति की नियमित समीक्षा पर ज़ोर दिया। आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्कों की समीक्षा करते हुए उन्होंने आत्मनिर्भरता मज़बूत करने के लिए सक्रिय औषधीय घटकों (एक्टिव फ़ार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स) और आवश्यक इनपुट के घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने मुख्य सचिवों से हर महीने ज़िलाधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा करने को कहा, कहा कि शासन का ध्यान परिव्यय के बजाय परिणामों पर होना चाहिए, और आकांक्षी ज़िला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए वंचित क्षेत्रों में विकास तेज़ करने में अभिसरण, नियमित निगरानी और स्थानीय जवाबदेही की भूमिका को रेखांकित किया; उन्होंने यह भी कहा कि शासन मज़बूत करने और कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी सुधारने के निरंतर प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की समीक्षा के दौरान उन्होंने देश भर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने का आह्वान किया और कहा कि पुनर्विकसित स्टेशन मेट्रो और परिवहन के अन्य साधनों से निर्बाध संपर्क वाले मल्टीमॉडल परिवहन केंद्र बनें।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329801

17 एनपीपीए ने कैंसर रोधी दवाओं के 543 ब्रांडों के संशोधित एमआरपी जारी किए; 9 नवंबर 2026 से प्रभावी

NPPA releases revised MRPs for 543 brands of anti-cancer medicines, effective from 9 November 2026

SSC • Railway • General

28 अक्टूबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के अधीन राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने कैंसर रोधी दवाओं के 543 ब्रांडों की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) के साथ एक सूची जारी की है, जो 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी। सूची में 27 अक्टूबर 2026 तक कंपनियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी शामिल है, और जैसे-जैसे निर्माता गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की अपनी संशोधित कीमतें प्रस्तुत करेंगे, इसे अपडेट किया जाएगा; एनपीपीए पोर्टल लगातार अपडेट किया जाता है। रिलीज़ में दिए गए उदाहरणों में एनाज़ोल (एनास्ट्रोज़ोल 1 एमजी) की 10 गोलियों के पैक का एमआरपी 695.76 रुपये से संशोधित होकर 73.00 रुपये, और बेवाकिज़ाब (बेवाकिज़ुमैब) के 100 मिलीग्राम/4 मिलीलीटर इंजेक्शन की शीशी का एमआरपी 21,767.70 रुपये से संशोधित होकर 5,930.13 रुपये हुआ है। 17 अक्टूबर 2026 को एनपीपीए ने अत्यधिक व्यापार मार्जिन को दूर करने, कैंसर के इलाज को अधिक किफ़ायती बनाने और कैंसर रोधी दवाओं तक पहुँच बेहतर करने के लिए जनहित में 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (टीएमआर) की घोषणा की थी और निर्माताओं को अपनी संशोधित सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इन 137 दवाओं में 20 से अधिक प्रकार के कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाली इम्युनोथेरेपी दवाएँ, स्तन और प्रोस्टेट कैंसर के रोगियों द्वारा उपयोग की जाने वाली डेनोसुमैब, कैंसर रोगियों में न्यूट्रोपेनिया रोकने के लिए उपयोग होने वाली पेगफिलग्रैस्टिम, और कोलन, अंडाशय (डिम्बग्रंथि) और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के इलाज के लिए अनुमोदित बेवाकिज़ुमैब शामिल हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329698

18 पीएमईजीपी के तहत 11,333 नए सूक्ष्म उद्यमों की सहायता के लिए 1,000 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी जारी

Rs 1,000 crore margin money subsidy released under PMEGP to support 11,333 new micro enterprises

SSC • Banking • General

28 अक्टूबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-3 में मंत्रालय द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 1,000 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी जारी की; कार्यक्रम में एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी उपस्थित थीं। इस सब्सिडी से 11,333 लाभार्थियों को सहायता मिलेगी, जिन्हें नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए लगभग 3,260 करोड़ रुपये के बैंक-स्वीकृत परियोजना ऋण मिले हैं, और इन उद्यमों से मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 1.02 लाख से अधिक स्थायी रोज़गार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह सहायता महिला-नेतृत्व वाली उद्यमिता, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों में सामाजिक रूप से समावेशी विकास, और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) तथा आकांक्षी ज़िलों पर विशेष ध्यान के साथ संतुलित क्षेत्रीय विकास पर लक्षित है। इस राशि के जारी होने से पहले वित्त वर्ष 2026-27 में अक्टूबर 2026 तक पीएमईजीपी 794.52 करोड़ रुपये की एमएम सब्सिडी के साथ 25,895 सूक्ष्म उद्यमों को सहायता दे चुका था। पीएमईजीपी गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों के ज़रिए स्वरोज़गार के अवसर पैदा करने वाला ऋण-संबद्ध (क्रेडिट-लिंक्ड) सब्सिडी कार्यक्रम है; इसका प्रशासन एमएसएमई मंत्रालय करता है और राष्ट्रीय स्तर पर इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) लागू करता है, जबकि केवीआईबी, ज़िला उद्योग केंद्र और कॉयर बोर्ड अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों में शामिल हैं। वित्त वर्ष 2014-15 से इसके तहत 70,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक-स्वीकृत ऋणों और 25,193 करोड़ रुपये से अधिक की एमएम सब्सिडी के माध्यम से 8.38 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यम स्थापित हुए हैं, जिनसे लगभग 75 लाख स्थायी रोज़गार के अवसर पैदा हुए; लगभग 80% इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, लगभग 50% लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों से हैं, और लगभग 40% उद्यमों की स्वामी महिला उद्यमी हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329819

19 भारतीय नौसेना के नौसैनिक नवाचार एवं स्वदेशीकरण सम्मेलन का पांचवां संस्करण, स्वावलंबन 2026, नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में संपन्न

Swavlamban 2026, the fifth edition of the Indian Navy's Naval Innovation and Indigenisation Seminar, concludes at the Manekshaw Centre, New Delhi

SSC • Railway • Defence • General

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नौसेना के प्रमुख नौसैनिक नवाचार एवं स्वदेशीकरण सम्मेलन (Naval Innovation and Indigenisation Seminar) का पांचवां संस्करण, स्वावलंबन 2026, 27 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में संपन्न हुआ। 'नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति एवं सामर्थ्य' (Strength & Power through Innovation and Indigenisation) विषय पर आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में रक्षा बलों, उद्योग जगत, स्टार्ट-अप, एमएसएमई, शिक्षाविदों और निवेशकों ने उभरती प्रौद्योगिकियों, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और भारत के रक्षा नवाचार तंत्र को मज़बूत करने पर विचार-विमर्श किया। पहले दिन की शुरुआत प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी के उद्घाटन और नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन द्वारा प्रदर्शनी के अवलोकन से हुई; प्रदर्शनी में सफल नवाचारों की कहानियाँ (सक्सेस स्टोरीज़), समुद्री निगरानी, काउंटर-यूएएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम प्रौद्योगिकी, एनबीसीडी और सुरक्षा, तथा कार्यक्षमता बढ़ाने वाली तकनीकों (एफिशिएंसी एन्हांसर्स) जैसे विषयगत क्षेत्रों में स्वदेशी नवाचार प्रदर्शित किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्ण सत्र में मुख्य अतिथि थे, जहाँ उन्होंने सम्मेलन के प्रख्यात वक्ताओं और आईडेक्स नवप्रवर्तकों को सम्मानित किया, और स्वावलंबन 5.0 दस्तावेज तथा 'प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं, समस्या विवरणों एवं भविष्य की अवधारणाओं' के संकलन (Compendium of Technology Imperatives, Problem Statements and Future Concepts) का विमोचन हुआ। दूसरे दिन दो संवादात्मक सत्र हुए: 'भविष्य और उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ', जिसमें मानवरहित प्रणालियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका तथा क्वांटम और हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकियों पर चर्चा हुई, और 'आत्मनिर्भरता और नवाचार के लिए आईडेक्स रक्षा तंत्र को बढ़ावा देना', जिसमें मानवरहित प्रणालियों के लिए प्रणाली अभियांत्रिकी, परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, बड़े रक्षा प्लेटफ़ॉर्मों में स्टार्ट-अप के नवाचारों को शामिल करने और स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करने पर बल दिया गया; आईडेक्स का पूरा नाम इनोवेशन्स फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार) है। घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करना, उद्योग-शिक्षा जगत सहयोग को सुगम बनाना और स्टार्ट-अप तथा एमएसएमई की अधिक भागीदारी सक्षम करना, रक्षा क्षेत्र में स्थायी आत्मनिर्भरता के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में उभरे।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2330137

आज का अभ्यास — 5 प्रश्न

प्र.1 26 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री ने लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर बधाई दी?

(A) अर्जेंटीना
(B) ब्राज़ील
(C) चिली
(D) मेक्सिको

प्र.2 27 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की?

(A) विजय कुमार चौधरी
(B) सी. आर. पाटिल
(C) शुभेंदु अधिकारी
(D) स्वतंत्र देव सिंह

प्र.3 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, 28 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में एराइज़ सिटीज़ फ़ोरम में स्वीकृत दिल्ली घोषणापत्र 2026 किस शहर में होने वाले कॉप31 तक जाएगा?

(A) अंताल्या
(B) बेलेम
(C) इस्तांबुल
(D) बाकू

प्र.4 सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, पूर्वोत्तर को दूध, अंडा, मछली और मांस के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए निर्धारित किया गया है?

(A) 2030
(B) 2035
(C) 2028
(D) 2047

प्र.5 एमएसएमई मंत्रालय की 28 अक्टूबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार 11,333 लाभार्थियों की सहायता के लिए पीएमईजीपी के तहत 1,000 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी जारी की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर पीएमईजीपी को कौन-सा निकाय लागू करता है?

(A) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
(B) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)
(C) विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय
(D) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)

उत्तर: 1-(B) 2-(B) 3-(A) 4-(A) 5-(B)

रोज़ सुबह 7 बजे यही PDF Telegram पर: t.me/parikshasaathiapp — चैनल से जुड़ें और दोस्तों को भेजें

रोज़ का PDF: parikshasaathi.com/daily-pdf — सभी संस्करण: parikshasaathi.com/downloads/

वेबसाइट: parikshasaathi.com (हिंदी + English में 248 पाठ, रोज़ का करंट अफेयर्स, परीक्षा नोटिस)

ऐप: Pariksha Saathi — Free, Offline, SSC/Bank की पूरी तैयारी। प्रकाशक: Mahesh Srivastava, Founder. सामग्री आधिकारिक विज्ञप्तियों से AI की सहायता से तैयार; किसी विषय-विशेषज्ञ संपादक द्वारा समीक्षित नहीं। ग़लती दिखे तो parikshasaathi.com/contact/ पर बताएँ।